देश की अर्थव्यवस्था में 10% हो यूपी की हिस्सेदारी

- मुख्यमंत्री योगी ने आर्थिक स्थिति, विकास संरचना और राजस्व की समीक्षा की
- लक्ष्य प्राप्त करने को ठोस रणनीति बनाने का निर्देश
- 2024-25 में राज्य का जीएसडीपी 29.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 29.6 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी 8.4 से बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था में राज्य की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होने पर राज्य का जीएसडीपी 41.84 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

सोमवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास संरचना और राजस्व स्रोतों की समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में प्रदेश की जीएसडीपी में 80 प्रतिशत वृद्धि दिख रही है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी निरंतर बढ़ रही है, जबकि कृषि क्षेत्र की लगातार कम हो रही है। 'मेक इन यूपी' माडल को अगले दशक के लिए औद्योगिक रणनीति का आधार बताते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े पूरी तरह प्रमाणिक और अपडेट होने चाहिए। कृषि, विनिर्माण, सेवा, ऊर्जा और मानव संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए स्पष्ट, समयबद्ध और परिणाम देने वाले रोडमैप तैयार किए जाएं। इनकी सतत् समीक्षा की जाए।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 722 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2020-21 की तुलना में 100 लाख टन अधिक है। मुख्यमंत्री ने जिलेवार उत्पादकता में अंतर को कम करने पर जोर दिया। विनिर्माण क्षेत्र की समीक्षा में बताया गया कि पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या वर्ष 2024-25 में 27 हजार से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनिर्माण को जिलों में समान रूप से प्रसारित किया जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और राज्य को राजस्व मिले। उन्होंने ज़िला उद्योग केंद्रों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। 2024-25 में राज्य से 46,800 करोड़ रुपये मूल्य की आइटी सेवाओं का निर्यात हुआ, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक है। पर्यटन, होटल और व्यापार जैसे सेवा क्षेत्रों में भी सकारात्मक संकेत देखे गए।

दो प्रमुख राजस्व स्रोतों-जीएसटी और आबकारी शुल्क की समीक्षा भी हुई। वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा एकत्रित जीएसटी 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत अधिक है। आबकारी से 52,574 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। इस राजस्व में प्रति वर्ष करीब 15 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी बस सेवाओं के लिए नए रूट चिह्नित किए जाएं जिससे आम लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ ही राजस्व के नये स्रोत बनेंगे। परिवहन क्षेत्र में रोजगार की भी बड़ी संभावनाएं हैं।